स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एवं अन्य

बनाम

विनेश कुमार भसीन

(2010 की सिविल अपील संख्या 1718)

22 जनवरी 2010

[आर.वी. रवीन्द्रन और के.एस. राधाकृष्णन, जे.जे.]

विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, सुरक्षा का अधिकार और पूर्णभागीदारी अधिनियम, 1995

अधिनियम की प्रयोज्यता -बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने से तीन दिन पहले, बैंक की 'एग्जिट पॉलिसी स्कीम' के तहत कार्यमुक्त होने के लिए आवेदन दाखिल करता है - अनुरोध स्वीकार नहीं होने पर, कर्मचारी आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराता है विकलांगजन, देहरादून और मुख्य आयुक्त के साथ विकलांग व्यक्ति, नई दिल्ली - कर्मचारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका और अवमानना याचिका दायर की - माना: कर्मचारी के आचरण पर टिप्पणी की जानी चाहिए-हालांकि वह देहरादून में सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने इलाहाबाद

उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की नई दिल्ली में जारी एक अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए-उन्होंने लगातार शिकायतें दर्ज की, बैंक को उपस्थित होने और कारण बताने का अवसर दिए बिना, तीन महीने से कम समय के भीतर रिट याचिका और अवमानना याचिका - वह एक विकलांग व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को उजागर करके बार-बार सहानुभूति जगाने और एकतरफा अंतरिम आदेश हासिल करने में सफल रहे, लेकिन असफल रहे। पूर्ण या सही तथ्यों का खुलासा करने के लिए - विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों और शिकायतों पर अदालतों और अधिकारियों द्वारा दया, समझ और शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए लेकिन अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी राहत या लाभ की तलाश में सेवा में नहीं डाला जा सकता है जहां शिकायत या शिकायत एक कथित भेदभाव से संबंधित है, जिसका व्यक्ति की विकलांगता से कोई लेना-देना नहीं है - न ही विकलांग व्यक्तियों की सभी शिकायतें विकलांगता के आधार पर भेदभाव से संबंधित हैं - यह तथ्य कि कर्मचारी ने विकलांग व्यक्ति होने का दावा किया है, ने डिप्टी को प्रभावित किया है मुख्य आयुक्त एवं उच्च न्यायालय की अनदेखी करना किसी भी कानूनी अधिकार का अभाव, और एक अंतरिम उपाय देने के लिए जिस पर सामान्य प्रक्रिया में विचार नहीं किया गया होगा - अंतरिम आदेश जारी करना जब आवश्यक न हो, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता विकलांग व्यक्ति है, अंतरिम आदेश जारी करने में असफल होने के समान ही घातक है। वारंट - न्याय प्रशासन-वादी का

आचरण सही तथ्यों का खुलासा न करना - अंतरिम आदेश। [पैरा 18 और 19]

धारा. 47, 58, 59, 61, 62 और 63 साथ पढ़ें आर.42 - अनिवार्य/निरोधात्मक निषेधाज्ञा जारी करने के लिए अधिनियम के तहत अधिकारियों की शक्ति - माना गया: न तो मुख्य आयुक्त और न ही अधिनियम के तहत कार्यरत किसी भी आयुक्त के पास कोई अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति है। या निषेधात्मक निषेधाज्ञा या अन्य अंतरिम निर्देश - तथ्य यह है कि विकलांगता अधिनियम उन्हें अपने कार्यों के निर्वहन के लिए एक नागरिक अदालत की कुछ शक्तियों (जिसमें शिकायतों को देखने की शक्ति भी शामिल है) के साथ प्रदान करता है, उन्हें एक नागरिक की अन्य शक्तियों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं बनाता है। न्यायालय जो अधिनियम द्वारा उनमें निहित नहीं हैं - तत्काल मामले में, सेवानिवृत्ति के आदेश को लागू न करने का उप मुख्य आयुक्त का आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था - इसके अलावा, दावेदार ने 'एग्जिट' का लाभ देने के लिए आवेदन दायर किया पॉलिसी स्कीम' सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने से तीन दिन पहले - वह अधिकार के रूप में, तीस साल की सेवा से अधिक जारी रखने का हकदार नहीं था - वास्तव में, वह सेवा में बने रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी शिकायत थी कि उसे ऐसा

करना चाहिए 'एग्जिट पॉलिसी स्कीम' के तहत सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है - कर्मचारी की शिकायत का उसके विकलांग व्यक्ति होने से कोई लेना-देना नहीं है - प्रथम दृष्टया न तो धारा 47 और न ही अधिनियम का कोई प्रावधान आकर्षित हुआ - उप प्रमुख आयुक्त ने एक पक्षीय निर्देश जारी करते समय इस तथ्य को नज़रअंदाज और नजरअंदाज कर दिया कि सेवा से सेवानिवृत्ति सेवा नियमों के अनुसार सेवा की निर्धारित अवधि पूरी करने पर होती है, जिसका स्पष्ट उल्लेख सेवानिवृत्ति पत्र दिनांक 17.11.2006 में किया गया था और कब एक कर्मचारी को नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त किया गया था, सेवानिवृत्ति की आयु से परे उसे सेवा में जारी रखने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है - विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 - आर.42 - राज्य बैंक ऑफ पटियाला (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 विनियम 19 - स्टेट बैंक ऑफ पेटी अला - 'निकास नीति योजना' - अंतरिम निषेधाज्ञा/दिशा-निर्देश - सेवा कानून। [पैरा 11 और 13]

ऑल इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक एससी और एसटी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1996 (8 सप्ल। एससीआर 295 1996(6) धारा 606 पर निर्भर।

भारत का संविधान 1950

अनुच्छेद 136-उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील-आमतौर पर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के एकपक्षीय अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि रिट या अवमानना कार्यवाही में प्रतिवादी उपस्थित हो सकता है और अवकाश या समाप्ति या संशोधन की मांग कर सकता है। ऐसा एक पक्षीय आदेश लेकिन जहां विशेष और असाधारण विशेषताएं या परिस्थितियां हैं जिनके परिणामस्वरूप अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है - तत्काल मामला ऐसी विशेष और दुर्लभ श्रेणी में आता है - कर्मचारी हालांकि बैंक के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त हुआ विकलांग व्यक्ति के टैग का उपयोग करके कार्यवाही की एक श्रृंखला शुरू करके बैंक और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को वस्तुतः आतंकित करने का प्रयास किया है और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके एक पक्षीय अंतरिम आदेश सुरक्षित करना विकलांगता अधिनियम के तहत कार्य करने वाले मुख्य आयुक्त अपने रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय और अपने अवमानना क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय ने एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किए हैं जिससे बैंक और उसके अधिकारियों को यह करने की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया कोई मामला न बनने पर बैंक के नियमों के विपरीत कार्य करना। (पैरा 10

अनुच्छेद 226 - उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार - अंतरिम आदेश - बैंक कर्मचारी विनियमों के अनुसार सेवानिवृत्त हुए - कर्मचारी द्वारा

विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को की गई शिकायतों पर कि एक्जिट पॉलिसी स्कीम के तहत राहत देने का उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था बैंक को कारण बताओ नोटिस और अंतरिम निर्देश जारी किए गए - रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने 12 01 2007 को बैंक को उप मुख्य आयुक्त द्वारा पारित अंतरिम निर्देशों के कार्यान्वयन का आदेश दिया - माना अनिवार्य अंतरिम आदेश केवल असाधारण मामलों में जारी किए जाते हैं जहां ऐसा करने में विफलता अपरिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय स्थिति को जन्म देगी - सेवानिवृत्ति से संबंधित सेवा मामलों में एकतरफा अनिवार्य निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है - तत्काल मामले में जब रिट याचिका से पता चला कि कर्मचारी 30 के बाद सेवानिवृत्त हुआ था बैंक के नियमों के अनुसार सेवा के वर्षों में किसी भी अपूरणीय चोट या तात्कालिकता का कोई सवाल ही नहीं था - तथ्यों और परिस्थितियों पर उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर नोटिस का निर्देश देते समय एक पक्षीय आदेश जारी नहीं करना चाहिए था जो वास्तव में बराबर है बैंक को सुने बिना रिट याचिका को अनुमति देना - उचित कदम यह होता कि बैंक को अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर दिया जाता विशेष रूप से क्योंकि न्यायालय को स्वयं मुख्य आयुक्त के अधिकार क्षेत्र और अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र के बारे में संदेह महसूस हुआ - इसके अलावा, उप मुख्य आयुक्त ने नई दिल्ली में आदेश जारी किया जबकि कर्मचारी देहरादून में कार्यरत था और देहरादून में सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था - जाहिर तौर पर

उत्तर प्रदेश राज्य में कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ-आदेश दिनांक 12 01 2007 है इसलिए अस्थिर - विकलांग व्यक्ति (समान अवसर] अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995-स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अधिकारी सेवा विनियम 1979 विनियम 19-अंतरिम आदेश कार्रवाई का कारण -उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। पैरा 14-15

न्यायालय की अवमानना

बैंक कर्मचारी द्वारा रिट याचिका - इस आधार पर कि उन्हें (एग्जिट पॉलिसी स्कीम) के लाभ से वंचित कर दिया गया और विकलांग व्यक्तियों के लिए उप मुख्य आयुक्त द्वारा पारित अंतरिम निर्देशों को लागू नहीं किया गया - उच्च न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस 15 2 2007 को वापस किया जा सकता है - लेकिन 13 2 2007 को] उच्च न्यायालय ने बैंक के शाखा प्रबंधक को अवमानना नोटिस जारी किया] निर्धारित किया गया: अवमानना कार्यवाही में कोई अंतरिम निर्देश जारी करने से पहले, या किसी को अवमानना का दोषी ठहराने का प्रस्ताव करने से पहले, उच्च न्यायालय को कम से कम खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि व्यक्ति को जिसे नोटिस जारी किया गया है वह आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार है - प्रतिवादी को सेवानिवृत्त करने का आदेश शाखा प्रबंधक द्वारा पारित नहीं किया गया था और जाहिर तौर पर वह वह अधिकारी नहीं था

जो उप मुख्य आयुक्त या उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश को लागू कर सकता था - अवमानना याचिका इसलिए] समय से पहले था - इसके अलावा] नोटिस जारी करने के चरण में उच्च न्यायालय यह नहीं मान सकता था कि जानबूझकर अवज्ञा की गई थी - सभी घटनाओं में दिनांक 12 1 2007 का आदेश अनुचित था] व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए निर्देश उक्त आदेश का अनुपालन करने में विफलता पर कायम नहीं रखा जा सकता - विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर] अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम] 1995 & भारत का संविधान] 1950 अनुच्छेद 226 (पैरा 16-17)

केस कानून संदर्भ

1996 (8) पूरक एससीआर 295 निर्भर पैरा 13

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 1718 ऑफ 2010

इलाहाबाद लखनऊ स्थित उच्च न्यायालय के 2007 की डब्ल्यू पी संख्या 40 मे पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12 01 2007 से।

साथ

सीआरएलए- नंबर 170 ऑफ 2010-

विष्णु मेहरा] साक्षी गुप्ता और प्रमोद दयाल अपीलकर्ता।

अरविंद कुमार गुप्ता] बिपिन बी- सिंह] असीम चंद्रा] विनोद कुमार और जॉयदीप मजमुदार प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया

आर- वी- रवीन्द्रन जे-

1 छुट्टी स्वीकृत (सुना गया)

2. प्रतिवादी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (संक्षेप में 'बैंक') का कर्मचारी था। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 19 में प्रावधान है कि एक अधिकारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या तीस वर्ष की सेवा पूरी होने पर, जो भी पहले हो, बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक अधिकारी उस महीने के आखिरी दिन सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह निर्धारित सेवा या सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लेगा। जैसे ही प्रतिवादी ने 17.11.2006 को तीस साल की सेवा पूरी की, बैंक ने दिनांक 17.11.2006 को एक आदेश दिया जिसमें प्रतिवादी को उक्त विनियमों के विनियम 19 के तहत 30.11.2006 से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

3. बैंक ने 1.12.2005 को एक 'निकास विकल्प योजना' तैयार की थी, जिसका उद्देश्य पात्र अधिकारियों को बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करके बैंक के कर्मचारियों की संख्या में कमी लाना था, जो कैरियर की

संभावनाओं की कमी के कारण हतोत्साहित हो सकते थे। उक्त योजना के तहत किसी अधिकारी की सेवा से रिहाई तभी प्रभावी होती है जब नामित प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी के अनुरोध को मंजूरी दे दी जाती है, ऐसे अधिकारी को सूचित किया जाता है। प्रतिवादी जो 18.11.1976 को बैंक की सेवा में शामिल हुआ और 17.11.2006 को सेवानिवृत्त होने वाला था, उसने उक्त योजना के तहत कार्यमुक्त होने के लिए दिनांक 14.11.2006 को आवेदन किया। चूंकि उक्त आवेदन तीस साल की सेवा पूरी होने से बमुश्किल तीन दिन पहले किया गया था, इसलिए जाहिर तौर पर उस पर कार्रवाई करने का समय नहीं था और इस पर कार्रवाई होने से पहले ही वह सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। बैंक के अनुसार, सेवानिवृत्ति की नियत तारीख से कुछ दिन पहले इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि करियर की संभावनाओं की कमी के कारण किसी कर्मचारी के उस स्तर पर हतोत्साहित महसूस करने का कोई सवाल ही नहीं है।

4. यह आरोप लगाते हुए कि 'एग्जिट ऑप्शन स्कीम' के तहत राहत पाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार करना गैरकानूनी था, प्रतिवादी ने दो शिकायतें कीं, पहली दिनांक 17.11.2006 को विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, देहरादून को और दूसरी दिनांक 20.11 को। .2006 में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, नई दिल्ली (संक्षेप में 'मुख्य आयुक्त') को बैंक की 'निकास विकल्प योजना' के तहत राहत देने के लिए बैंक को

निर्देश देने की मांग की गई। उन्होंने उक्त आवेदन में दावा किया कि वह 26.5.1997 को एक सड़क दुर्घटना में शामिल थे और परिणामस्वरूप, विकलांग व्यक्ति बन गए; और यह कि बैंक ने एग्जिट पॉलिसी स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति के लिए उनके आवेदन को स्वीकार नहीं करके, उनकी विकलांगता के कारण उनके साथ भेदभाव किया।

5. उप मुख्य आयुक्त, नई दिल्ली ने बैंक को दिनांक 22.11.2006 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि मुख्य आयुक्त ने विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। भागीदारी) अधिनियम, 1995, (संक्षेप में 'विकलांगता अधिनियम') बैंक से यह कारण बताने के लिए कहा गया है कि उसे विनियम 19 के तहत सेवानिवृत्त होने के बजाय, 'निकास विकल्प योजना' के तहत प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार करने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। निर्देश दिया कि प्रतिवादी को सेवा से सेवानिवृत्त करने के बैंक के निर्णय को अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाना चाहिए।

6. बैंक ने दिनांक 23.12.2006 को यह कहते हुए आपत्ति दर्ज की कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है और इसमें कोई योग्यता नहीं है। बैंक ने यह भी बताया कि उप निदेशक द्वारा दिनांक 22.11.2006 को भेजा गया

कारण बताओ नोटिस। मुख्य आयुक्त के साथ न तो शिकायत की प्रति थी और न ही उस आदेश की प्रति, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मुख्य आयुक्त द्वारा किया गया था। हमें सूचित किया गया है कि मुख्य आयुक्त ने मामले में कोई और आदेश पारित नहीं किया है।

7. इस आधार पर कि बैंक ने मुख्य आयुक्त के अंतरिम निर्देश का पालन नहीं किया, प्रतिवादी ने 10.1.2007 को (2007 की डब्ल्यूपी संख्या 40 (एसबी) दाखिल करके) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और बैंक को निर्देश देने की मांग की। मुख्य आयुक्त के आदेश का पालन करें और बैंक और उसके अधिकारियों (अर्थात उप महाप्रबंधक, दिल्ली क्षेत्र, अतिरिक्त महाप्रबंधक, III (डी) लखनऊ, और शाखा प्रबंधक, देहरादून, जो यहां अपीलकर्ता 2 से 4 हैं) को आदेश देने वाला एक परमादेश का पालन करें।), उसे वेतन देने और उसे काम करने की अनुमति देने के लिए। उच्च न्यायालय ने 12.1.2007 को अपीलकर्ताओं को नोटिस देने का आदेश दिया और एक पक्षीय अंतरिम आदेश भी जारी किया कि मुख्य आयुक्त के निर्देश का अनुपालन किया जाए, इस टिप्पणी के साथ कि यदि बैंक द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा। मामला अगली बार सूचीबद्ध है। उक्त अंतरिम आदेश के अनुपालन हेतु कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई।

8. इस आधार पर कि दिनांक 12.1.2007 के उक्त एकतरफा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, प्रतिवादी फिर से अवमानना याचिका के साथ उच्च न्यायालय में पहुंच गया। उस याचिका में, उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.2.2007 को एक पक्षीय आदेश दिया, जिसमें बैंक की देहरादून शाखा के शाखा प्रबंधक को 3.4.2007 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, यदि रिट याचिका में जारी अंतरिम आदेश दिनांक 12.1.2007 सही नहीं था। तब तक संकलित किया गया।

9. दिनांक 12.1.2007 के आदेश से व्यथित होकर, बैंक और उसके अधिकारियों ने 2007 की एसएलपी (सी) संख्या 6124 दायर की है। अवमानना कार्यवाही में उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, बैंक के दो अधिकारी जिन्हें नोटिस दिया गया है 2007 की एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 1870 जारी की गई है। इस न्यायालय ने 23.4.2007 को दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जैसा कि प्रतिवादी प्रारंभिक सुनवाई के समय वकील के माध्यम से उपस्थित हुआ, इस न्यायालय ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी नवंबर, 2006 में 30 साल की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो गया था और प्रतिवादी की दलील दर्ज की गई कि वह बिना किसी पूर्वाग्रह के सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसके अधिकारों के लिए. तदनुसार,

प्रतिवादी को सेवानिवृत्ति लाभ जारी कर दिए गए हैं और अवमानना कार्यवाही पर 18.8.2008 को रोक लगा दी गई

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

10. आमतौर पर यह न्यायालय उच्च न्यायालय के एक पक्षीय अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि रिट या अवमानना कार्यवाही में प्रतिवादी उपस्थित हो सकता है और ऐसे एक पक्षीय आदेश की छुट्टी, या समाप्ति, या संशोधन की मांग कर सकता है। लेकिन जहां विशेष और असाधारण विशेषताएं या परिस्थितियां हैं जिनके परिणामस्वरूप या अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है, यह न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। ये मामला ऐसे ही खास और दुर्लभ श्रेणी में आता है. प्रतिवादी, हालांकि बैंक के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त हो गया है, 'विकलांग व्यक्ति' के टैग का उपयोग करते हुए, उसने कार्यवाही की एक श्रृंखला शुरू करके और गलत तरीके से प्रस्तुत करके एक पक्षीय अंतरिम आदेश हासिल करके बैंक और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को वस्तुतः आतंकित करने का प्रयास किया है। तथ्य। विकलांगता अधिनियम के तहत कार्य करने वाले मुख्य आयुक्त, अपने रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय और अपने अवमानना क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय ने एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें बैंक और उसके अधिकारियों को बैंक के नियमों के विपरीत कार्य करने की आवश्यकता होती है, जबकि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं होता है। बाहर

कर दिया। आइए हम इनमें से प्रत्येक क्रमिक एक पक्षीय अंतरिम आदेश से निपटें।

मुख्य आयुक्त का अंतरिम निर्देश

11. नियमों के तहत, बैंक का एक अधिकारी 30 साल की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त होगा। तदनुसार, प्रतिवादी को तीस वर्ष पूरे होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया। उन्हें किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित नहीं किया गया। अधिकार के तौर पर वह तीस साल से अधिक सेवा जारी रखने का हकदार नहीं था। दरअसल, वह सेवा में बने रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी शिकायत थी कि उन्हें एग्जिट पॉलिसी स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। प्रतिवादी की शिकायत का जाहिर तौर पर उसके विकलांग व्यक्ति होने से कोई लेना-देना नहीं था। प्रथम दृष्टया न तो धारा 47 और न ही विकलांगता अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान आकर्षित हुआ। लेकिन, मुख्य आयुक्त ने शिकायत पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया और सेवानिवृत्ति के आदेश को प्रभावी न करने का एक पक्षीय निर्देश भी जारी किया। उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि सेवा से सेवानिवृत्ति सेवा नियमों के अनुसार सेवा की निर्धारित अवधि पूरी होने पर होती है, जिसका स्पष्ट उल्लेख सेवानिवृत्ति पत्र दिनांक 17.11.2006 में किया गया था; और जब किसी कर्मचारी को नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त किया गया था, तो उसे

सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में जारी रखने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। मुख्य आयुक्त ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि विकलांगता अधिनियम के तहत कार्य करने वाले एक प्राधिकारी के रूप में, उनके पास नियोक्ता को किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त न करने का निर्देश जारी करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है। वास्तव में, विकलांगता अधिनियम की योजना के तहत, मुख्य आयुक्त (या आयुक्त) के पास कोई अंतरिम निर्देश देने की शक्ति नहीं है।

12. मुख्य आयुक्त के कार्य अधिनियम की धारा 58 और 59 में निर्धारित हैं। धारा 58 में प्रावधान है कि मुख्य आयुक्त के निम्नलिखित कार्य होंगे: -

(ए) आयुक्तों के काम का समन्वय करना;

(बी) केंद्र सरकार द्वारा वितरित धन के उपयोग की निगरानी करना;

(सी) विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना;

(डी) सरकार द्वारा निर्धारित अंतराल पर अधिनियम के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

धारा 59 में प्रावधान है कि धारा 58 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त अपनी इच्छा से या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा शिकायतों पर गौर कर सकता है और उपयुक्त अधिकारियों के साथ

मामले को उठा सकता है, (ए) से संबंधित कोई भी मामला विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का हनन; और (बी) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त सरकारों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बनाए गए या जारी किए गए कानूनों, नियमों, उप-कानूनों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशानिर्देशों या निर्देशों का कार्यान्वयन न करना। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त आयुक्तों के पास भी धारा 61 और 62 के तहत समान शक्तियां हैं। धारा 63 में प्रावधान है कि मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के पास इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए वही शक्तियां होंगी जो एक अदालत में निहित हैं। किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निम्नलिखित मामलों के संबंध में: (ए) गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना; (बी) किसी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता; (सी) किसी अदालत या अधिकारी से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना; (डी) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; और (ई) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना। विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 का नियम 42 मुख्य आयुक्त द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है।

13. उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि न तो मुख्य आयुक्त और न ही विकलांगता अधिनियम के तहत कार्यरत किसी भी आयुक्त के पास कोई

अनिवार्य या निषेधात्मक निषेधाज्ञा या अन्य अंतरिम निर्देश जारी करने की शक्ति है। तथ्य यह है कि विकलांगता अधिनियम उन्हें अपने कार्यों के निर्वहन के लिए सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियों (जिसमें शिकायतों पर गौर करने की शक्ति भी शामिल है) प्रदान करता है, उन्हें सिविल कोर्ट की अन्य शक्तियां ग्रहण करने में सक्षम नहीं बनाता है जो उनमें निहित नहीं हैं। विकलांगता अधिनियम के प्रावधान. ऑल इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक एससी और एसटी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1996 (6) एससीसी 606 में, यह न्यायालय, भारत के संविधान के (अनुच्छेद 338 (8)विकलांगता अधिनियम की धारा 63 के समान) से निपट रहा है। , इस प्रकार मनाया गया:

"यह खंड (8) को स्पष्ट रूप से पढ़ने से देखा जा सकता है कि आयोग के पास उप-खंड (ए) में विचारित जांच करने और उप-खंड (ए) में संदर्भित शिकायत की जांच करने के उद्देश्य से सिविल कोर्ट की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (5) के खंड (बी) । सिविल कोर्ट की सभी प्रक्रियात्मक शक्तियां इन मामलों की जांच और पूछताछ के उद्देश्य से आयोग को दी जाती हैं और वह भी केवल उस सीमित उद्देश्य के लिए। शक्तियां सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा देने का आयोग में कोई अधिकार नहीं है और न ही संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (8) को पढ़ने से ऐसी शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है ।

सेवानिवृत्ति के आदेश को क्रियान्वित न करने का मुख्य आयुक्त का आदेश अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहीन था।

रिट कार्यवाही में अंतरिम आदेश.

14. रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम एकपक्षीय आदेश देने से संबंधित सिद्धांत अच्छी तरह से तय हैं। अदालतों को इस धारणा पर यांत्रिक तरीके से अंतरिम आदेश नहीं देना चाहिए कि पीड़ित पक्ष हमेशा छुट्टी मांग सकता है। एकतरफा अंतरिम आदेश देना, वह भी अनिवार्य आदेश, नियमित रूप से या केवल मांगने के लिए, सहानुभूति के आधार पर या अन्यथा, न्याय के हितों की सेवा करने के बजाय प्रशासनिक अराजकता को जन्म देने वाले न्याय में हस्तक्षेप करेगा। जहां रिट याचिका प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनती है या जहां रिट याचिका की स्थिरता या अदालत के क्षेत्राधिकार या दावे की वैधता के बारे में कोई संदेह है, उच्च न्यायालय कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगा, वह भी जब कोई अपूरणीय क्षति या चोट न हो. सभी घटनाओं में, उच्च न्यायालय एक पक्षीय अनिवार्य निषेधाज्ञा या निर्देश जारी करने से बचेगा जिसका वस्तुतः उत्तरदाताओं को सुने बिना याचिका को एक पक्षीय अनुमति देने का प्रभाव होगा। अनिवार्य अंतरिम आदेश असाधारण मामलों में ही जारी किए जाते हैं, जहां ऐसा करने में विफलता से अपरिवर्तनीय या सुधार योग्य स्थिति पैदा हो जाएगी। सेवानिवृत्ति से संबंधित सेवा मामलों में, एकपक्षीय

अनिवार्य निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब रिट याचिका में खुलासा हुआ कि प्रतिवादी को बैंक के नियमों के अनुसार 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया था, तो किसी भी अपूरणीय चोट या तात्कालिकता का कोई सवाल ही नहीं था।

15. तथ्यों और परिस्थितियों पर हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के अंतरिम निर्देश के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस देने का निर्देश देते समय एक पक्षीय आदेश जारी नहीं करना चाहिए था। जो वस्तुतः बैंक को सुने बिना रिट याचिका को अनुमति देने के समान है। उचित कदम यह होगा कि बैंक को अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर दिया जाए, विशेषकर इसलिए क्योंकि न्यायालय को स्वयं मुख्य आयुक्त के अधिकार क्षेत्र और अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र के बारे में संदेह महसूस हुआ। मुख्य आयुक्त ने नई दिल्ली में आदेश जारी किया। प्रतिवादी देहरादून में कार्यरत था और देहरादून में सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। स्पष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य में वाद-कारण का कोई भाग उत्पन्न नहीं हुआ। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें। इसलिए हमने माना कि दिनांक 12.1.2007 का आदेश टिकाऊ नहीं है।

<u>अवमानना कार्यवाही में अंतरिम आदेश.</u>

16. अवमानना याचिका में प्रतिवादी की शिकायत यह थी कि बैंक ने 12.1.2007 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एकपक्षीय अंतरिम आदेश की अवज्ञा की थी। उच्च न्यायालय द्वारा अपने अंतरिम आदेश के अनुपालन के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। रिट याचिका में कारण बताओ नोटिस 22.1.2007 को जारी किया गया था जो 15.2.2007 को वापस किया जा सकता है। लेकिन उस तारीख से पहले ही, प्रतिवादी ने अनुपालन न करने की शिकायत करते हुए अवमानना याचिका दायर की। नोटिस जारी करने और बैंक या बैंक के अधिकारियों को एक अवसर देने के बजाय, उच्च न्यायालय ने 13.2.2007 को निम्नलिखित आदेश पारित किए:

> "विपक्षी पक्ष नंबर 2 (बैंक के शाखा प्रबंधक) को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करें कि 12.1.2007 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने के लिए उसे अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 2 के तहत दंडित क्यों नहीं किया जा सकता है, जो कि अब तक इसका अक्षरश: अनुपालन नहीं किया गया है। यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो उन्हें 3 अप्रैल 2007 को अभिलेख सहित उपस्थित होना होगा।"

अवमानना कार्यवाही में कोई अंतरिम निर्देश जारी करने या किसी को अवमानना का दोषी ठहराने का प्रस्ताव करने से पहले, उच्च न्यायालय को कम से कम खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है वह आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। प्रतिवादी को सेवानिवृत्त करने का आदेश शाखा प्रबंधक द्वारा पारित नहीं किया गया था और जाहिर तौर पर वह वह अधिकारी नहीं था जो मुख्य आयुक्त या उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश को लागू कर सकता था।

17. हमारा मानना है कि अवमानना याचिका अपरिपक्व थी। हमारा यह भी विचार है कि नोटिस जारी करने के चरण में उच्च न्यायालय यह नहीं मान सकता था कि जानबूझकर अवज्ञा की गई है। सभी घटनाओं में, हमारे निर्णय के परिणामस्वरूप कि दिनांक 12.1.2007 का आदेश अनुचित था, दिनांक 12.1.2007 के आदेश का अनुपालन करने में विफलता पर व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

<u>प्रतिवादी के आचरण से उचित टिप्पणियाँ</u>

18. प्रतिवादी के आचरण पर टिप्पणी करना आवश्यक है। 30 वर्ष की सेवा के बाद दिनांक 17.11.2006 के आदेश द्वारा उन्हें 30.11.2006 से सेवानिवृत्त कर दिया गया। उन्होंने 17.11.2006 को देहरादून, उत्तराखंड में विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त को एक शिकायत दी। उन्होंने

20.11.2006 को मुख्य आयुक्त, नई दिल्ली को एक और शिकायत की। हालाँकि वह देहरादून में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्होंने नई दिल्ली में जारी अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उन्होंने बैंक को पेश होने और कारण बताने का मौका दिए बिना, तीन महीने से भी कम समय के भीतर लगातार शिकायतें, रिट याचिका और अवमानना याचिका दायर कीं। वह विकलांग व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बार-बार उजागर करके सहानुभूति जगाने और एकपक्षीय अंतरिम आदेश हासिल करने में सफल रहे, लेकिन पूर्ण या सही तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहे।

19. विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों और शिकायतों पर अदालतों और अधिकारियों द्वारा दया, समझ और शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए। वे सम्मानपूर्वक जीवन चाहते हैं। विकलांगता अधिनियम कुछ सकारात्मक कार्यों के माध्यम से उन्हें समान अवसर प्रदान करना चाहता है ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार के मामलों में पर्याप्त अवसर मिल सकें। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के साथ उनकी विकलांगता के कारण भेदभाव न करना सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है। लेकिन विकलांगता अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी राहत या लाभ की तलाश में लागू नहीं किया जा सकता है जहां शिकायत या शिकायत कथित भेदभाव से संबंधित है, जिसका व्यक्ति की विकलांगता से कोई लेना-देना

नहीं है। न ही विकलांग व्यक्तियों की सभी शिकायतें विकलांगता के आधार पर भेदभाव से संबंधित हैं।

चित्रण :

आइए एक ऐसे मामले पर विचार करें जहां किसी संगठन में सेवानिवृत्ति की आयु सभी द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए 58 वर्ष और सभी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए 60 वर्ष है। जब एक द्वितीय श्रेणी अधिकारी, जो विकलांग व्यक्ति होता है, यह विवाद उठाता है कि ऐसी असमानता भेदभाव के बराबर है, तो इसका विकलांगता से कोई लेना-देना नहीं है। विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति और बिना विकलांगता वाले व्यक्ति भी अदालत में यह तर्क दे सकते हैं कि ऐसा प्रावधान भेदभावपूर्ण है। लेकिन, ऐसा प्रावधान, भले ही यह भेदभावपूर्ण हो, इसका व्यक्ति की विकलांगता से कोई लेना-देना नहीं है और विकलांग व्यक्ति द्वारा इस तरह के भेदभाव के संबंध में राहत का दावा करने के लिए विकलांगता अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है।

बिना विकलांग व्यक्तियों की तुलना में विकलांग व्यक्ति अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, घृणा या गलतफहमी जैसी मानवीय कमजोरियों से कम पीड़ित नहीं होते हैं। उनकी कई शिकायतों और विवादों का विकलांगता से कोई लेना-देना नहीं हो सकता है। तथ्य यह है कि प्रतिवादी ने विकलांग व्यक्ति होने का दावा किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मुख्य आयुक्त और उच्च

न्यायालय को किसी भी कानूनी अधिकार की अनुपस्थिति को नजरअंदाज करने और एक अंतरिम उपाय देने के लिए प्रेरित किया है, जिस पर सामान्य प्रक्रिया में विचार नहीं किया जाता। आवश्यकता न होने पर अंतरिम आदेश जारी करना, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता विकलांग व्यक्ति है, आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम आदेश जारी करने में विफल रहने जितना ही घातक है।

निष्कर्ष

20. इसलिए हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और 2007 के डब्ल्यूपी नंबर 40 (एसबी) में उच्च न्यायालय के दिनांक 12.1.2007 के आदेश और सीआरएल में 13.2.2007 के आदेश में निहित अंतरिम निर्देशों को रद्द कर देते हैं। विविध. 2007 का केस नंबर 420 (सी)। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह यहां अपीलकर्ताओं (बैंक और उसके अधिकारियों) को सुनें और फिर 2007 और सीआरएल के डब्ल्यूपी नंबर 40 (एसबी) का निपटान करें। मिस. 2007 का केस नंबर 420(सी) कानून के मुताबिक।

21. यह स्पष्ट किया गया है कि इस अदालत के समक्ष लंबित मामले के दौरान प्रतिवादी द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति कानून के अनुसार यह स्थापित करके किसी भी उपाय को अपनाने में बाधा नहीं बनेगी कि वह विकलांग व्यक्ति है और उसके साथ भेदभाव किया गया था। , उसकी

शिकायत/शिकायत पर विचार करने के लिए सक्षम मंच के समक्ष।

अपील की अनुमति.

अस्वीकरण

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री भरत पूनिया, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रजी संस्करण ही मान्य होगा।